युवाओं को आगे बढ़ाने पर फोकस, स्टार्टअप्स बनेंगे रीढ़

इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने व स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपये का सीड फंड

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ स्टार्टअप्स बनेगा। यही वजह रही कि बजट में सरकार ने युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने और आगे बढ़ाने पर खास्सा फोकस किया है। युवा उद्यमियों को आगे बढ़ाने और स्टार्टअप को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने बजट में कई घोषणाएं की हैं।

वर्तमान में 50 इन्क्यूबेटर और 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत हर क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर व नोएडा परिसर में

₹60

करोड़ उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी व स्टार्टअप्स नीति के लिए

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने व स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ के सीड फंड का बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी व स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपये

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के युवा उद्यमियों को भी स्टार्टअप की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है। इसके तहत एग्रीक्लस्टर एक्सीलेटर फंड की शुरुआत 20 करोड़ से की गई है। कृषि शिक्षा, शोध व अनुसंधान के लिए प्रदेश के चार कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना को प्रभावी बनाया जाएगा। इसके तहत इन क्षेत्रों में काम व शोध किया जाएगा। ताकि कृषि की समस्याओं को तकनीकी के माध्यम से भी सुलझाया जा सके।

उद्योगों के लिए 31 हजार युवाओं का प्रशिक्षण

डिप्लोमा व स्नातक डिग्रीधारक प्रशिक्षुओं के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत युवाओं को उद्योगों के लिए प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य विवि व महाविद्यालयों में स्किल हब

राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बजट में स्किल हब की स्थापना की भी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्र-छात्राओं को स्किल्ड करने की कवायद इसके द्वारा की जाएगी। इसके लिए एक लाख रुपये का प्रतीकात्मक बजट तय किया गया है।